the Government, especially of the Ministry of Human Resource Development to the great hardship caused to the pensioners of Central universities, as their pensions have not yet been revised although the Central Government has announced the rules several months ago under which these employees were entitled to get enhanced pensions and arrears were also to be paid to them. I have received this information from the pensioners of Muslim University, Aligarh, that necessary instructions have not been issued so far by the University Grants Commission to the Muslim University authorities to pay to pensioners pensions at new rates under the revised rules. It means that neither the enhanced pensions are being paid nor arrears of pensions have been paid to the pensioners. This is really distressing and shocking that the University Grants Commission should take so much time in sending the necessary innstructions. Surely, this cannot be called efficiency. Why has so much time been taken by the U.G.C. in sending necessary instructions? This has resulted in non-payment of pensions to poor retired teachers and other employees of the universities. This is a sad commentary on the working of the U.G.C. which must be removed.

Through you Madam, I shall request the Minister of Human Resource Development to take immediate action in this matter and help the poor pensioners of the Muslim University, Aligarh, and other Central universities. Further, he should see to it that the U.G.C. works more efficiently by giving up its time-consuming, slowmoving and dilatory methods.

Construction of Unauthorised structures in Delhi

श्री लक्ष्मी नारायण (दिल्ली) : उपसभापति महोदया, अक्सर देखने में आया है कि जब भी नाजायज या गैर-कानूनी तौर पर मकान बनते हैं, चाहे डी०डी०ए० हो चाहे कारपोरेशन हो चाहे नई दिल्ली नगरपालिका हो, इनके जो संबंधित अधिकारी हैं वे काफी आराम से बैठे रहते हैं और जब चार सौ या पांच सौ मकान इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरी पुलिस लेकर इस तरीके से मकान तोड़ने के लिये जाते हैं जैसे शायद वे आकुपाइड कश्मीर को खाली कराने जा रहे हों । फिर वहां ला एंड आर्डर की समस्या होती है – लाठी चार्ज होता है, टियर गैस छोड़ी जाती है, पथराव होता है जिसमें कि मकान मालिक भी मरते हैं और पुलिस वाले भी मरते है । उसके बाद सीज फायर के आर्डर होते हैं और लगता है कि डी०डी०ए० के इन्हीं दुष्कर्मों की वजह से भगवान भी नाराज हो गये हैं जिसके कारण मानसून दिल्ली में नहीं आया है । क्या इन लोगों को समझाया जा सकता कि कुछ अच्छे काम करें ? जब एक या दो मकान बनते हैं उस वक्त ये लोग क्या करते है ? क्या तीर्थ यात्रा पर गये हुये होते हैं, दिल्ली के बाहर होते हैं ? जब पांच सौ मकान बन जाते हैं तभी तोड़ने का नाम लेते हैं ।

मैडम आपने कभी फिल्म देखी होगी । फिल्म ढाई घंटे की होती है ; उस ढाई घंटे में शादी भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, वह बच्चा हीरो भी बन जाता है । वहां ढाई घंटे में सब कुछ हो जाता है तो आप क्या ढाई घंटे में मकान नहीं तोड़ सकते ? अगर ढाई घंटे में नहीं तोड़ सकते तो आप ढाई दिन ले लीजिये, ढाई महीने ले लीजिये । लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि जब मकान बन जायें, उनमें बिजली भी लग जाय, पानी भी उनको दे दिया जाय, सीवर लाइन भी बन जाये, सड़कें बननी शुरू हो जायें तो आप यह कहेंगे कि हम इनको तोड़ेंगे क्योंकि ये बस गये हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डी०डी०ए० को इसके लिये हिदायत दे । जैसे पिछले महीने में दिल्ली म आतंक मचा, सैकड़ों मकान तोड़े गये, तो उनसे पूछा जाना चाहिये कि वे लोग तब कहां गये थे । इसी तरह से सड़कों का हाल है ... (व्यवधान)

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : (हरियाणा) : मंत्रियों के इलाकों में मकान बन रहे हैं तो...

श्री लक्ष्मी नारायण : मेरे इलाके में तो बनते नहीं हैं । मैं तो उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि आप खाली करेंगे तो वहां जाऊंगा ।.... (**व्यवधान**)

महोदया, दिल्ली में आम तौर पर सावन के महीने में बरसात होती है, चारों और हरियाली होती है । लेकिन दिल्ली में धूल भरी आंधी चलती है। इसका कारण खोजने की कोशिश नहीं की गई । ये आपके अधिकारियों के निकम्मे काम है जिसके कारण दूसरे शरीफ लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है फसल नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो क्या होगा । करता कोई है, भरता कोई है । करने वाले मुट्ठी भर हैं लेकिन उसका परिणाम दिल्ली के 60 लाख लोग भुगत रहे हैं । पसीने में लोगों की जान निकल रही है, बीमारी शुरू हो जायेगी, फिर अगर डाक्टरों ने हड़ताल नहीं की तो लोग ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर के पास जायेंगे कि हमारी मदद करो ।

इसी तरह से सड़कों की मरम्मत के नाम पर उनको खोद दिया जाता है, लेकिन उनको ठीक करने का कोई नाम नहीं लेता कि किसी जमाने में सड़क खोदी गई थी उसको ठीक भी करना है । नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक ब्लाक होता है, दुर्घटनायें होती हैं, भागदौड़ होती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के कानों पर जूं नहीं रेंगती । क्या यह किया जा सकता कि जिस इलाके में दो महीने से ज्यादा समय तक सड़कें खुदी पड़ी रहेंगी, वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या सेक्शनल आफिसर को जिम्मेदार बनाया जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ? ऐसा करके ही दिल्ली की जनता को मुसीबतों से बचाया जा सकता है ।

U.S. Move to establish Bases in Pakistan

श्री कल्पनाथ राय : (उत्तर प्रदेश) उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक विशेष उल्लेख द्वारा गंभीर प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

महोदया, अमरीकी रक्षा पत्रिका "डिफेंस वीक" के अनुसार अमरीकी केन्द्रीय कमान का मुख्यालय स्थापित करने की दृष्टि से पाकिस्तान आदर्श जगह हो सकता है, खासकर तब जब कि सभी अरब देश अपनी भूमि पर अमरीका को अड्डा बनाने की सुविधा देने में आनाकानी कर रहे हैं

पत्रिका के अनुसार – पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल जिया उल हक को इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय करना है, क्योंकि इससे अरब देशों के बीच जहां पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी वहीं पाकिस्तान में अमरीका का विरोध बढ़ेगा ।

पत्रिका के अनुसार – अमरीका इस समय पाकिस्तान पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वह खाड़ी में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करे । अमरीका चाहता है कि खाड़ी के क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका बढ़े ।

पत्रिका के अनुसार अमरीका विदेश उप मंत्री माइकेल आर्मकोस्ट की पाकिस्तान यात्रा से पहले अमरीकी केन्द्रीय कमान के कमांडर इन चीफ जनरल जार्ज क्राइस्ट भी पाकिस्तान आये थे, लेकिन उनकी यात्रा गुप्त रखी गई ।

पत्रिका ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जनरल क्राइस्ट इस क्षेत्र में ऐसा अड्डा खोज रहे हैं जहां वह कमान मुख्यालय और नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर सकें । अभी तक फलोरिडा के टाम्पा में केन्द्रीय कमान का मुख्यालय है । फिलहाल पाकिस्तान केन्द्रीय कमान के जहाजों को ईंधन तथा अन्य नौसैनिक सुविधायें मुहैया कराता है । आदरणीय उपसभापति महोदया, अमेरिका अपनी अन्तर्राष्ट्रीय गोबल स्ट्रेटजी के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों में अपने अड्डे बना रहा है । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अभी श्री लंका हिन्दुस्तान